











# संपादकीय

## सियासी मंच पर जनमंच

**सवाल** जनमंच को उपयागित सेनिकला और इसको बिसात में भी सियासत बिछ गई। विधानसभा सत्र के बहाने फिर राजनीति के मंच पर चढ़ा। जनमंच। इसके पक्ष और विरोध में हुए राजनीतिक मुकाबले से दूर कहीं आम आदमी के सवालों का विशेषण होता तो व्यवस्था भी सही होती। शिकायत को माइक की जरूरत है या सरकारों के पास शिकायती कान होने चाहिए, जो प्रक्रिया के बजाय मंच पर बजें। बेशक आंकड़ों में जनमंच पर 39726 शिकायतें चढ़ीं, लेकिन इससे सुशासन को मुँह छुपाने का बहाना भी मिल गया। इतनी शिकायतों का समाधान अगर जनमंच की प्रासंगिकता बता रहा या यह साबित कर रहा कि रूटीन में दफ्तर असफल हो रहे, तो यह व्यवस्था की कृशलता तो नहीं है। हम अगर जनमंच को सही विकल्प

सरकार की मौजूदगी में जनमंच भले ही ऊचे संबोधनों की विरासत में राजनीतिक लाभ चुन लें, लेकिन प्रशासन की मौलिकता, पारदर्शिता, ईमानदारी व पवित्रता को इससे आंका नहीं जा सकता। सुशासन पर मोहर तब लगेगी जब विभागों के लक्ष्य इन्हीं के दायित्व में पूरे होंगे। सुशासन की पहचान के लिए मंच से उत्तर कर फ़िल्ड को देखना पड़ेगा ताकि पता चले कि लोक निर्माण विभाग के कार्यों की गुणवत्ता क्या है। जलशक्ति विभाग की परियोजनाओं का मुआयना करके ही पता चलेगा कि जलाधूर्ति कितनी दोषपूर्ण है। बस मैं जब मंत्री चलेंगे तो एचआरटीसी की दिक्कतें पता चलेंगी। जनमंच केवल शिकायतों को मौका देता है, जबकि प्रशासन के भीतर बहुत सारे कर्मचारी-अधिकारी वर्षों से अपने दायित्व की मिसाल हैं, तो उनको श्रेय देने के लिए क्या कोई पद्धति बनी।

राजनीतिक लाभ चुन लें, लेकिन प्रशासन की मौलिकता, पारदर्शिता, ईमानदारी व पवित्रता को इससे आंका नहीं जा सकता। सुशासन पर मोहर तब लगेगी जब विभागों के लक्ष्य इन्हीं के दायित्व में पूरे होंगे। सुशासन की पहचान के लिए मंच से उत्तर करने वाले फील्ड को देखना पड़ेगा ताकि पता चले कि लोक निर्माण विभाग के कार्यों की गुणवत्ता क्या है। जलशक्ति विभाग की परियोजनाओं का मुआयना करके ही पता चलेगा कि जलाधार्पूर्ति कितनी दोषपूर्ण है। बस में जब मंत्री चलेंगे तो एचआरटीसी की दिक्कतें पता चलेंगी। जनमंच के बल शिकायतों को मौका देता है, जबकि प्रशासन के भीतर बहुत सारे कर्मचारी-अधिकारी वर्षीय से अपने दायित्व की मिसाल हैं, तो उनको श्रेय देने के लिए क्या कोई पद्धति बनी। सरकारें अगर अपनी स्थानांतरण नीति या नियम ही तय नहीं कर पाएंगी, तो मंच सजा कर कोसाने के सिवाय मिलेगा भी क्या। क्या बोरोजगारों को जनमंच रोजगार दे पाएगा या जब भर्ती घोटाले या कर्मचारी चयन आयोग में पैपल लीक हो रहे थे, तो क्या किसी जनमंच ने इनके कान पकड़े। शिकायतें तो व्यापारी, दुकानदार या हर निजी व्यापार में ढेरों हैं, तो क्या कभी इनके पास कोई जनमंच गया। जनमंच एक अच्छा आयोजन हो सकता और अगर सत्ता को भीड़ इक्कीं करके खुद को भांपना है तो भी यह सुखद अनुभव हो सकता है, लेकिन क्या जनमंच को आम नागरिक हमेशा अपने नजदीक बुला सकता है। उसके नजदीक तो पंचायत कार्यालय है, जहां सचिव मौजूद होना चाहिए। उसके नजदीक पटवारी, डिस्ट्रेसरी में डाक्टर-नर्स, स्कूल में अध्यापक-शिक्षा, जलाधार्पूर्ति के लिए फिटर, विद्युत आपूर्ति के लिए लाइनमैन और कानून व्यवस्था के लिए पास में कोई पुलिस चौकी या थाना होता है, लेकिन यह सही तरह से उसे सुनें उसके लिए हर दिन तो जनमंच नहीं हो सकता। जनमंच के माध्यम से खुशफहमी हो सकती है या कोई बजीर कुछ क्षण के लिए आपांखो सकता है, लेकिन देखें कि राज्य सचिवालय में आर्बाटिट कार्यालयों में हमारे मंत्री नियमित रूप से कितने दिन बैठते हैं। जिला के अधिकारियों को जनमंच सजाने, बंदोबस्त करने व खाल बचाने के लिए अधिकांश समय निकल जाएगा, तो फिर दफ्तरों को अलविदा कर दें। ऐसे में वर्तमान मुख्यमंत्री अगर विभागीय तथा दफ्तरी माहौल में सरकारी कार्यसंस्कृति को उत्तरदायी व जवाबदेह बनाने के लिए सार्वजनिक प्रक्रिया को चुस्त-दुरुस्त करें, तो ही बदलाव आएगा।

# कुछ अलग

## लगा पोस्टर, निकली सियासत

**राजधानी** दिल्ली की दीवारों पर अचानक कुछ पोस्टर चिपका दिए गए-'मोदी हातो, देश बचाओ।' यह कोई देश-विरोधी नारा नहीं है और न ही चुनावी मौसम में अप्रत्याशित माना जा सकता है। भारतीय लोकतंत्र में ऐसे नारों और पोस्टरों की परंपरा नहरू-कालखंड से रही है। 1962 में भारत-चीन युद्ध जारी था, लेकिन तब विपक्षी जनसंघ ने तकालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नहरू के खिलाफ नारों और पोस्टरों का अभियान छेड़ा था। आपातकाल के दौरान जयप्रकाश नारायण ने यह भी नारा दिया था- 'इंदिरा हातो, देश बचाओ।' उस दौर में पोस्टर ही नहीं छापे गए, बल्कि काली स्टार्ही से दीवारों पर भी नारे लिखे गए। भारतीय राजनीति में और भी उदाहरण होंगे, लेकिन दिल्ली में प्रधानमंत्री-विरोधी पोस्टर नजर आए, तो पुलिस ने करीब 140 प्राथमिकियां दर्ज कर लीं और 30 से अधिक लोगों को गिरफ्तार भी किया गया।

यह उसलासला अमा जारा ह। यकानन प्राथमिका क सदम मध्य आकड़ झूमूरूपूर्व है, क्योंकि पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराना टेही खीर है। पहले और अब की राजनीति में फर्क इतना ही है कि 2009 में एक कानून बनाया गया था। उसके मुताबिक, किसी भी पोस्टर पर प्रिंटिंग प्रेस और प्रकाशक का नाम छापना अनिवार्य है और पोस्टरों की संख्या सार्वजनिक करना भी लाजिमी है। ऐसा नहीं करना 'अपराध' माना जाता है। कुछ घंटों तक यह रहस्य बना रहा कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पोस्टर-अभियान किसने छेड़ा है? लेकिन 'आम आदमी पार्टी' (आप) के दफ्तर से पोस्टरों से भरी एक वैन निकल रही थी, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया। बाद में 'आप' के कुछ मंत्रीनुमा नेताओं ने भी कबूल किया कि पोस्टर 'आप' ने ही छपवाए हैं। यह प्रधानमंत्री का विरोध-अभियान है, क्योंकि उन्होंने देश को ठगा है और अपने वायदे परे नहीं किए हैं। 'आप' ने यह मौका जानबूझ कर चुना है, क्योंकि पोस्टर कांड के अगले ही दिन 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सरीखे क्रांतिकारियों का 'शहीदी दिवस' था। इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के जरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान समेत 'आप' के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने 'जंतर-मंतर' पर विरोध-प्रदर्शन भी किया। बहरहाल पोस्टरकांड से दो बुनियादी सावाल उभरते हैं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी वाकई तानाशाह, कायर, मनारोही हैं, जैसा कि 'आप' के नेता बयान दे रहे हैं? दूसरे, क्या पोस्टरबाजी के जरिए चुनाव जीता जा सकता है और 2024 का आम चुनाव 'मोदी बनाम के जरीवाल' होगा? दरअसल हम 'आप' की राजनीति से सहमत नहीं हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल की गई भाषा 'लोकतात्रिक' नहीं है। दूसरे, 'मोदी बनाम के जरीवाल' का चुनावी समीकरण भी 'हास्यास्पद' है। लोकसभा में 'आप' का एक भी संसद नहीं है। 2019 के आम चुनाव में 'आप' ने कुल 35 उम्मीदवार उतारे थे। उनमें से सिर्फ एक सीट पर भगवंत मान जीत पाए थे। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उस सीट पर उपचानाव हआ। जिसमें 'आप' हार गई।

**जलवायु परिवर्तन के कारण 2000 से बाढ़ की घटनाओं में 134 प्रतिशत वृद्धि हुई।**  
**भारत की प्राचीन जल संस्कृति को जीवंत करें।**

ललित गर्ग

पानी के संरक्षण और समुचित  
उपलब्धता को सुनिश्चित कर हम  
पर्यावरण को भी बेहतर कर सकते हैं  
तथा जलवायु परिवर्तन की समस्या  
का भी समाधान निकाल सकते हैं।  
पैकेट और बोतल बन्द पानी आज  
विकास के प्रतीकचिह्न बनते जा रहे हैं  
और अपने संसाधनों के प्रति हमारी  
लापरवाही अपनी मूलभूत  
आवश्यकता को बाजारवाद के हवाले  
कर देने की राह आसान कर रही है।  
विशेषज्ञों ने जल को उन प्रमुख  
संसाधनों में शामिल किया है, जिन्हें  
भविष्य में प्रबंधित करना सबसे  
चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। सदियों से  
निर्मल जल का स्त्रोत बनी रही नदियाँ  
प्रदूषित हो रही हैं, जल संचयन तंत्र  
बिगड़ रहा है, और भू-जल स्तर  
लगातार घट रहा है।

भारत में धार्मिक आस्थाओं से खिलवाड़ करके देशद्रोह का काम करने वाले द्वोहियों की सूची काफी लंबी है। इसी खला में देश की सुरक्षा एजेंसियों को अभी तक इस्लाम के कथित उपदेशक जाकिर नाइक की तलाश है जाकिर नाइक पर भारत में भड़काऊ भाषण देने, मनी लॉन्ड्रिंग करने और आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप है। मई 2019 में ईडी ने जाकिर नाइक के खिलाफ टेरर फंडिंग मामले में चार्जशीट दायर की थी। नाइक 2016 से भारत से बाहर है। उसके खिलाफ भारतीय एजेंसियों ने नोटिस जारी किया है। इसी तरह ईसाई धर्म की आड़ में धार्मिक आस्थाओं को भुना कर अपने नापाक मंसूबे पूरे करने के प्रयास के मामले में तमिलनाडु के कन्याकुमारी में एक रोमन कैथोलिक पादरी जाँज पोन्नैया को गिरफ्तार किया गया था। पादरी पोन्नैया पर धार्मिक समूहों के बीच नफरत और दुश्मनी फैलाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, डीएमके नेता एवं अन्य के खिलाफ विवादित टिप्पणी

23

**हेसौरम् व्याधिः** जो कई गाड़ियों से कि गालों को तैयार पायलों का बक गाल

**बेमौसम** बारिश से देश में  
तैयार फसलों ।  
ओलावृष्टि के कारण करोड़ों बाल हैं। कुदरत ने निवाला छीन लिया।  
फसलों को सही कीमत नहीं मिल सकता। बर्बाद कर रहे हैं। उपर से मौसम की  
कमर टूटती जा रही है। पिछले दिन  
बारिश से फसलों को नुकसान हुआ।  
चिंता बढ़ गई है। किसानों की माली है।  
कर्ज में डबे किसानों पर बेमौसम  
तैयार फसल सड़ गल गई है। तमाम

**जल** प्रदूषण एवं पीने के स्वच्छ जल की निरन्तर घटती मात्रा को लेकर बड़े खतरे खड़े हैं। धरती पर जीवन के लिये जल सबसे जरूरी वस्तु है, जल है तो जीवन है। जल ही किसी भी प्रकार के जीवन और उसके अस्तित्व को संभव बनाता है। जीव मंडल में पारिस्थितिकी संतुलन को यह बनाये रखता है। पीने, नहाने, ऊर्जा उत्पादन, फसलों की सिंचाई, सीधेज के निपाटन, उत्पादन प्रक्रिया आदि बहुत उद्देश्यों को पूरा करने के लिये स्वच्छ जल बहुत जरूरी है। जिन पाँच तत्वों को जीवन का आधार माना गया है, उनमें से एक तत्व जल है। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। मानव एवं जीव-जन्तुओं के अलावा जल कृषि के सभी रूपों और अधिकांश औद्योगिक उत्पादन प्रक्रियाओं के लिये भी बेहद आवश्यक है। परंतु आज पूरी दुनिया जल-संकट के साए में खड़ी है। अनियोजित औद्योगिक रण, बढ़ता प्रदूषण, घटते रेगिस्तान एवं ग्लोशियर, नदियों के जलस्तर में गिरावट, पर्यावरण विनाश, प्रकृति के शोषण और इनके दुरुपयोग के प्रति असंवेदनशीलता पूरे विश्व को एक बड़े जल संकट की ओर ले जा रही है। इसका उद्देश्य विश्व के सभी देशों में स्वच्छ एवं सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना है साथ ही जल संरक्षण के महत्व पर भी ध्यान केंद्रित करना है। आप सोच सकते हैं कि एक मनुष्य अपने जीवन काल में कितने पानी का उपयोग करता है, किंतु क्या वह इतने पानी को बचाने का प्रयास करता है? दुनिया की आवादी आठ अरब से अधिक हो चुकी है। इसमें से लगभग आधे लोगों को साल में कम से कम एक महीने पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ता है। जलवायु परिवर्तन के कारण 2000 से बाढ़ की घटनाओं में 134 प्रतिशत बढ़ि हुई है और सूखे की अवधि में 29 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। पानी के संरक्षण और समुचित उपलब्धता को सुनिश्चित कर हम पर्यावरण को भी बेहतर कर सकते हैं तथा जलवायु परिवर्तन की समस्या का भी समाधान निकाल सकते हैं। पैकेट और बोतल बन्द पानी आज विकास के प्रतीकचिह्न बनते जा रहे हैं और अपने संसाधनों के प्रति हमारी लापरवाही अपनी मूलभूत आवश्यकता को बाजारवाद के हवाले कर देने की राह आसान कर रही है। विशेषज्ञों ने जल को उन प्रमुख संसाधनों में शामिल किया है, जिन्हें



भावधृत करना सबसे चुनातापूर्ण काय हाँ। सदियों से निर्मल जल का स्रोत बनी रहीं नदियाँ प्रदूषित रही हैं, जल संचयन तंत्र बिगड़ रहा है, और भू-जल स्तर लगातार घट रहा है। धरती पर सुरक्षित और पीने के पानी बहुत कम प्रतिशत के आंकलन के द्वारा जल संरक्षण या जब बचाओ अभियान हम सभी के लिये बहुत जरूरी हो चुका औद्योगिक कचरे की वजह से रोजाना पानी के बड़े स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं। जल को बचाने में अधिक कार्यक्षमता लेने के लिये सभी औद्योगिक बिल्डिंगें, अपार्टमेंट्स, स्कूल और अस्पतालों आदि में बिल्डरों के द्वारा उचित जल प्रबन्धन व्यवस्था को बढ़ावा देना चाहिये। पीने के पानी या साधारणी की कमी के द्वारा होने वाली संभावित समस्या के बारे में आम लोगों को जानने के लिये जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाना चाहिये। जल की बाबूदी के बारे में लोगों के व्यवहार मिटाने के लिये इसकी त्वरित जरूरत है। इसी सप्ताह संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में जल सम्मेलन आयोजित हो रहा जिसमें सभी के लिए जल और स्वच्छता उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण चर्चा होगी। पानी धरती पर जीवन और अस्तित्व के लिए आधारभूत आशयकता है। आबादी में वृद्धि के साथ पानी की खपत बैतौहाश बढ़ी है, लेकिन पृथ्वी साफ पानी की मात्रा कम हो रही है। जलवायु परिवर्तन और धरती के बढ़ते तापमान ने इस समस्या को गंभीर संकट बढ़ाया है। इस सम्मेलन में सरकार, उद्योग जगत और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के लिए लक्ष्य तो निर्धारित किये जायेंगे, साथ ही आम लोगों को पानी बचाने के मुहिम जोड़ने के लिए भी कारगर कार्योजना बनाने पर विचार होगा। दुनिया के कई हिस्सों की तरह भारत भी जल संकट

# देश को क्षति पहुंचाने वाले ढोंगी और ढल

यह पहला मौका नहीं है जब धर्म की आड़ में हथियार जमा करके खालिस्तान समर्थक अमृतपाल जैसे स्वयंभू धार्मिक प्रचारक ने देश की एकता-अखंडता को चुनौती दी है। दरअसल ऐसे कथित बाबा और स्वयंभू पंथ प्रवर्तक जब तक राज्य और देश के लिए खतरा नहीं बन जाते तब तक पुलिस और अन्य एजेंसियां तमाशबीन बनी रहती हैं। धर्म के नाम पर होने वाले इस तरह के कारनामों से भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब हुई है। राजनीतिक दल ऐसे मुझे पर वोट खिसकने के भय से मौन साधे रहते हैं। ऐसे ढोंगियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में तभी लाई जाती है, जब राजनीतिक दलों को इनसे खतरा सताने लगता है। इससे पहले इनकी सारी आपराधिक हरकतें पर सरकारें वोट बैंक खिसकने के भय से चुप्पी साधे रहती हैं। ऐसा ही खालिस्तान समर्थक और संगठन 'वारिस पंजाब दे' के प्रमुख अमृतपाल के मामले में थुआ। यह मुद्दा सिरदर्द बनने के बाद सरकारें बगलें झांकने लगीं। धर्म की आड़ लेकर समानांतर सरकार चलाने का ख्वाब पालने वाले ऐसे कथित ढोंगियों को राजनीतिक दल शह देते आए हैं। जब पानी सिर से गुजरने लगता है, तब कार्रवाई की नौबत आती है। अमृतपाल ने जब सरेआम हथियारों के साथ प्रदर्शन किया, तब तक पुलिस कार्रवाई के लिए पंजाब सरकार का मुंह ताकती रही। केंद्र सरकार के



जारी किया है। इसी तरह ईसाई धर्म के अस्थाओं को भुना कर अपने नापाक मंसुबों के मामले में तमिलनाडु के कन्याकुमारी कैथोलिक पादरी जॉर्ज पॉन्नैया को गिरफ्तार किया गया। पादरी पॉन्नैया पर धार्मिक समूहों के बीच फैलाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री शशीकला दीप्ति एवं अन्य के खिलाफ विवादित आरोप लगे थे। ऐसा ही एक मामले में खुला वैगंशर बरताकर भविष्य में होने वाली घटना। करने का दावा करने वाले ठग पादरी बजिंदर अपनी ही फॉलोवर लड़की से दुष्कर्म के किया गया था। बजिंदर हत्या के मामले में उन्होंने धर्म गुरुओं ने कई बार लोगों की जान मध्यप्रदेश के रत्तालाम जिले के नयापुरा इयूम कर भगाने का दावा करने वाले मौलिंयनगुरु असलाम कोरोना से संक्रमित पाया गया। देन बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु सम्पर्क में आए 19 लोगों में से 4 की मौत हो गई। के संगीन मामलों में सजा काट रहे गुरमीत रमेश पुराना नहीं है। डेरा प्रमुख 2017 से हरियाणा में बंद है, जहां वह सिरसा में अपने आश्रम

सामना कर रहा है। वैश्वक जनसंख्या का 18 प्रतिशत हिस्सा भारत में निवास करता है, लेकिन चार प्रतिशत जल संसाधन ही हमें उपलब्ध है। भारत में जल-संकट की समस्या से निपटने के लिये प्राचीन समय से जो प्रयत्न किये गये हैं, वे दुनिया के लिये मार्गदर्शक हैं। देश के सात राज्यों के 8220 ग्राम पंचायतों में भूजल प्रबंधनों के लिए अटल भूजल योजना चल रही है। स्थानीय समुदायों के नेतृत्व में चलने वाला यह दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। साथ ही, नल से जल, नदियों की सफाई, अतिक्रमण हटाने जैसे प्रयास प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हो रहे हैं। जल संरक्षण की दिशा में बड़ी पहल करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने इस वर्ष जनवरी में राज्यों के जल मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया था। अब यह सम्मेलन हर साल आयोजित किया जाएगा। इसके उद्देश्यानन्दन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उचित ही रेखांकित किया कि सभी राज्यों को मिलकर काम करना होगा तथा जल संरक्षण एवं उपयोग किये गये पानी को फिर से इस्तेमाल में लाने के उपाय करने होंगे। हमारे यहां जल बचाने के मुख्य साधन हैं नदी, ताल एवं कूप। इन्हें अपनाओं, रक्षा करो, अभ्य दो, इन्हें मरुस्थल के हवाले न करो। अन्तिम समय यही तुम्हारे जीवन और जीवनी को बचायेंगे। ऊँचात पर्यावरणविद अनुपम मिश्र तो 'अब भी खरे है तालाब' कहते कहते स्वर्गस्थ हो गये। आज आवश्यकता इस बात की है कि विश्व जल दिवस की मूल भावना को अपने दैनिक जीवन में उतारकर हर व्यक्ति, हर दिन जल संरक्षण का यथासंभव प्रयास करे। गाँव के स्तर पर लोगों के द्वारा बरसात के पानी को इकट्ठा करने की शुरुआत करनी चाहिये। उचित रख-रखाव के साथ छोटे या बड़े तालाबों को बनाने के द्वारा बरसात के पानी को बचाया जा सकता है। धरती के क्षेत्रफल का लागभग 70 प्रतिशत भाग जल से भरा हुआ है। परंतु, पीने योग्य जल मात्र तीन प्रतिशत है। इसमें से भी मात्र एक प्रतिशत मीठे जल का ही वास्तव में हम उपयोग कर पाते हैं। पानी का इस्तेमाल करते हुए हम पानी की बचत के बारे में जरा भी नहीं सोचते, जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश जगहों पर जल संकट की स्थिति पैदा हो चुकी है। जल का संकट एवं विकट स्थितियां अति प्राचीन समय से बनी हुई हैं।

देश दुनीया से

## आत्मनिर्भर अस्तित्व के लिए आत्मनिर्भर पवंतीय राज्य को अपने प्राकृतिक संसाधनों के लिए लड़ना और राष्ट्रीय अनपात पर जमी

बर्फ को अपने पक्ष में हटाने को संघर्ष करना ही पड़ेगा। हिमाचल ने वाटर सेस के जरिए अपनी आर्थिकी के आत्मबल को जिस पटरी पर रखा है, वहां पंजाब व हरियाणा की मूँछे तनी हुई नजर आ रही हैं। आश्चर्य यह कि जो पंजाब कल तक हिमाचल की नदियों से निकले पानी की बैंदों पर हरियाणा के अधिकार पर ताला लगाने की हर मुमकिन कौशिश करता रहा है, उसे भी हिमाचल के आत्मनिर्भर अस्तित्व पर एतराज है। यह जलविवाद नहीं है और न ही पंजाब पुनर्गठन की आत्मा से कोई धोखा। सबसे पहले तो यही कि किसी सरकार ने पानी में बहती आर्थिकी को निचोड़ने की हिम्मत दिखाई है। अगर गैर से देखें तो पर्वतीय राज्यों को समझने में केंद्रीय नीतियों का भी दोष रहा है। आज तक न तो पानी को कच्चा माल स्वीकार करके ग्राफल्टी तथ हुई और न ही पर्वतीय जिम्मेदारियों व लेनदारियों के एवज में केंद्र सरकारों ने न्याय किया। हिमाचली अधिकारों की बात सर्वप्रथम शांता कुमार ने दिल्ली मार्च के माध्यम से उठाई थी, तो प्रेम कुमार धूमल के समय में आया औद्योगिक पैकेज एक खूबसूरत पैणाप रहा। विद्युत उत्पादन में मिलने वाली मुफ्त बिजली जरूर एक सांचे की तरह हिमाचल को आश्रय देती है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए इनसाफ की डगर पानी से निकलेगी या जंगल के बदले वित्तीय भरपाई का कोई

फामूला ढूढ़ना पड़गा। आश्चर्य यह कि हिमाचल वाटर सेस उन विद्युत इकाइयों से हासिल करना चाहता है जो प्रदेश की धरती पर स्थापित होने के बदले पहले ही हजारों लोगों को उजाड़ चुकी है। यह कैसे संभव हो सकता है कि उजड़े तो हिमाचल, लेकिन मालामाल केवल पड़ोसी राज्य ही होते रहे। पौंग डेम का ही उदाहरण ले, तो इससे एक यूनिट बिजली भी हिमाचल को नहीं मिली। यह कैसा दस्तूर कि सतलुज, ब्यास या रागों में बाढ़ आए तो दमापुर रेविन्यू दाक्षे तबाने

वित्तीय संरचना के आर्थिक संचार के लिए कठिन विकल्प चुनने होंगे और तीसरे युवा पीढ़ी को गैर सरकारी सेवा व स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनने का माहौल व प्रोत्साहन देना होगा। एक पानी पर सेस लगा कर हिमाचल को पता चल गया कि उसे 'पप्प' बना कर रखने वाली प्रवृत्तियां किस तरह व्यवहार करती हैं। हमें आत्मनिर्भर होने के लिए एक नई जमीन व वातावरण चाहिए और यह केवल जंगलों की मिलकीयत से मिलेगा। हम प्रदेश की 70

हमारा, लाकोन इसके बदल पड़ोसी राज्यों के अधिकार बरकरार रहेंगे। आज भी पंजाब पुनर्गठन की लकीरों में फंसे हिमाचल का 7.19 प्रतिशत हिस्सा इसलिए गुम है विद्योगिक न तो प्रदेश सरकारों ने संघर्ष को अंजाम तक पहुंचाया है और न ही केंद्र ने इमानदारी से प्रदेश के साथ इनसाफ किया। अब तो पर्वतीय राज्यों की वित्तीय मदद से पूरी तरह 90:10 की औसत से योजनाओं-परियोजनाओं के पोषण से भी केंद्र न-नुकर करने लगा है। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में वित्तीय पोषण की 50:50 प्रतिशत की शर्त से हिमाचल का शहरी विकास अवरुद्ध हुआ है। पड़ोसी राज्यों से जमीन जैसे मसले अगर नहीं सुलझे तो इसलिए भी कि केंद्र ने हमें महत्व ही नहीं दिया या हमारा प्रतिनिधित्व संसद में सेयो रहा। देश के लिए कुबनियों का इतिहास रचने वाले हिमाचल को न तो सैन्य संस्थान मिले और न ही आज तक राष्ट्रीय निर्माण योजनाओं में पूर्ण अधिकार मिले। सिफ्ट एक बार जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने राज्य को औद्योगिक पैकेज दिया था, तब लगाने लगा था कि

इसके माफत प्रदेश आर्थिक आधार पर खड़ा हो पाएगा, लेकिन बड़े राज्यों के विरोध के कारण यह भी अधूरे संकल्प के साथ समाप्त हो गया। हमारा मानना है कि प्रदेश को आर्थिक तौर पर आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले उस ताक-ज़ांक को छोड़ना होगा, जो केवल केंद्रीय रहमार्केट पर पल्लवित होती रही है। दूसरी ओर वित्तीय संरचना के आर्थिक संचार के लिए कठिन विकल्प चुनने होंगे और तोसेरे युवा पीढ़ी को गैर सरकारी सोच व स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनने का माहौल व प्रोत्साहन देना होगा। एक पानी पर सेस लगा कर हिमाचल को पता चल गया कि उसे 'पप्पू' बना कर रखने वाली प्रवृत्तियां किस तरह व्यवहार करती हैं। हमें आत्मनिर्भर होने के लिए एक नई जमीन व वातावरण चाहिए और यह केवल जंगलों की मिलकीयत से मिलेगा। हम प्रदेश की 70 फीसदी जमीन जंगलों को देकर हासिल क्या कर रहे हैं। सिर्फ यही कि चारे की कमी ने पशुओं को आवारा बना दिया या बंदरों ने जंगल से बाहर निकल कर हमारा जीवन उजाड़ दिया। जो पंजाब-हरियाणा जंगल के लिए मात्र चार फीसदी जमीन ही दे रहे हैं, उनका आर्थिक आधार हमसे बेहतर होगा, लेकिन मात्र तीस फीसदी जमीन की पत्रता में हिमाचल के हाथ क्यों बंधे रहे।



## गांधीवादी विचारधारा के साथ विश्वासघात : राहुल की सजा पर आया अमेरिकी सांसद का बयान

बॉशिंगटन ।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मजा और फिर लोकसभा सदस्यता जाने के मुद्दे पर जहां भारत में पूरा विपक्ष बिफर गया है, वहीं इसे लेकर अब संयुक्त राष्ट्र से लेकर अमेरिकी सांसद तक के बीच समाज की अपील है। भारतीय मूल के प्रभावशाली अमेरिकी संसद रो खन्ना ने राहुल गांधी को लोकसभा सदस्यता से अयोग्य घोषित किए जाने के फैसले को गांधीवादी विचारधारा के साथ 'गहरा विश्वासघात' करते दे दिया।

**क्या बोले अमेरिकी सांसद**

रो खन्ना ने दीटीट किया, राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जाना गांधीवादी दर्शन और भारत के गहरे

मूर्खों के साथ गहरा विश्वासघात है। उहोंने कहा, यह वह नहीं है, जिसके लिए मेरे दावाओं ने अपनी जिंदगी के कई साल जेल में कुर्बान कर दिए थे। रो खन्ना अमेरिका की प्रतिनिधित्व सभा में सिलिंगकॉन वैनी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह भारत और भारतीय-अमेरिकी पर अमेरिकी संसद के कांक्स के सह-अध्यक्ष हैं। उहोंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में हस्तांतरे करने का अनुरोध किया है।

रो खन्ना ने एक अन्य टीटीट में कहा, भारतीय लोकतंत्र के हित के लिए आपके पास इस फैसले को पलटने की शक्ति है। वहीं, अमेरिका में ईडिवन ऑफिसरों को गांधीवादी के उत्तराधिकारी के लिए एक दुखद दिन कराया जाए। उहोंने कहा, यह भारत में लोकतंत्र के लिए एक दुखद दिन कराया। उहोंने कहा, यह भारत में लोकतंत्र के

के लिए एक दुखद दिन है। राहुल गांधी को अयोग्य ठहराकर, मोदी सरकार हर जगह अधिक्यवित की आजादी और भारतीयों की आजादी के अधिकार के लिए मौत की घंटी बजा रही है।

**सजा पर आ युक्ता है यून का बयान**

राहुल गांधी को सूरत कोर्ट की ओर से सुनाई गई सजा का मामला यूपट तक पहुंच चुका है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटीनियो ग्रुपरेस के प्रबक्ता फरहान हक का इस मामले पर शुक्रवार को ही बयान आया था। उहोंने कहा था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सोल की जैल की सजा और कोर्ट के लिए इस फैसले के खिलाफ उनको दायरा डाया अपील करने की खबरों से संयुक्त राष्ट्र अवगत है।

### न्यूज़ ब्रिफ

अफगान छात्रों के स्कूल जाने से रोकने पर दुखी हुई पराष्ट्रपति कमला हैरिस, बोलीं- अमेरिका लड़कियों के साथ विशेषज्ञ। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस अफगानिस्तान में लड़कियों की माध्यमिक विद्यालय में उपरित्ति पर प्रतिवाद लगाए जाने से दुखी है। हैरिस ने टिवर पर कहा, दुनिया भर की लड़कियों और

महिलाओं के अधिकारों के लिए अमेरिका अपना समर्थन करना बढ़ नहीं करता। अमेरिका पहले भी अफगान महिलाओं की सिविल विकास के साथ अमेरिका खड़ा है। वहीं, उपरित्ति के उपर विद्यालय में भी तालिबान सरकार के लिए अपनी कक्षाओं में भाग लेने से प्रतिविवित कर दिया था।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि दिया का सामना रही है। अफगानिस्तान के अनुसार, महिलाओं के अधिकार अफगानिस्तान का एक आतंकी सुदूर है और विदेशी देशों को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस्लामिक अमीरत के प्रवक्ता जब्बाबुल मुजाहिद ने कहा, उन्हें कमीशन के लिए देश में ऐंबेसी या हाई कमीशन होती है, कि वहां दिल्लीमेंटस को काम करने के लिए सुरक्षा दी जाए। हाई कमीशन कैपेसिट की संसदी की आवाज रखा जाए। हाई कमीशन कैपेसिट की विद्यालय में भारतीय लोकसभा इंटरनेशनल का विद्यालय होता है। उपरित्ति के लिए देश में ऐंबेसी या हाई कमीशन होती है।

जब्बाबुल मुजाहिद ने कहा, उन्हें दिल्लीमेंट के लिए अपनी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि दिया का सामना रही है। अपनी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि दिया का सामना रही है। अपनी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि दिया का सामना रही है। अपनी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि दिया का सामना रही है।

प्राकिस्तान के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान, बोले- वित गंत्रालय के पास चुनाव कराने के पैरै ही नहीं है

इस्लामाबाद। प्राकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कहना है कि देश के वित गंत्रालय के पास चुनाव कराने के पैरै ही नहीं है।

प्राकिस्तानी मीडिया के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय ख्वाजा को एक बड़ा बोलते हैं - बैंगलुरु में एक युवा संघरक को संबोधित करते हैं देश में एक युवा संघरक को लोकतंत्र के लिए अपनी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि दिया का सामना रही है। वहीं सैन राष्ट्रपति को लोकतंत्र के लिए अपनी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि दिया का सामना रही है। अपनी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि दिया का सामना रही है।

हमले के बाद से हाई-कमीशन के बाहर सुरक्षा बढ़ी - प्रियंका ने कहा कि कुछ देशों को अपने नामिकों की सुरक्षा को लेकर अन्यता रखा है और दूसरे देशों को लोकतंत्र के लिए अपनी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि दिया का सामना रही है। वहीं विदेशी अमेरिकी ने एक राष्ट्रपति को लोकतंत्र के लिए अपनी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि दिया का सामना रही है।

जब्बाबुल मुजाहिद ने कहा कि दिया का सामना रही है। अपनी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि दिया का सामना रही है। अपनी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि दिया का सामना रही है।

प्राकिस्तानी मीडिया के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय ख्वाजा को एक बड़ा बोलते हैं - बैंगलुरु में एक युवा संघरक को संबोधित करते हैं देश में एक युवा संघरक को लोकतंत्र के लिए अपनी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि दिया का सामना रही है। वहीं सैन राष्ट्रपति को लोकतंत्र के लिए अपनी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि दिया का सामना रही है।

जब्बाबुल मुजाहिद ने कहा कि दिया का सामना रही है। अपनी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि दिया का सामना रही है।

प्राकिस्तानी मीडिया के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय ख्वाजा को एक बड़ा बोलते हैं - बैंगलुरु में एक युवा संघरक को संबोधित करते हैं देश में एक युवा संघरक को लोकतंत्र के लिए अपनी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि दिया का सामना रही है।

जब्बाबुल मुजाहिद ने कहा कि दिया का सामना रही है। अपनी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि दिया का सामना रही है।

प्राकिस्तानी मीडिया के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय ख्वाजा को एक बड़ा बोलते हैं - बैंगलुरु में एक युवा संघरक को संबोधित करते हैं देश में एक युवा संघरक को लोकतंत्र के लिए अपनी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि दिया का सामना रही है।

जब्बाबुल मुजाहिद ने कहा कि दिया का सामना रही है। अपनी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि दिया का सामना रही है।

प्राकिस्तानी मीडिया के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय ख्वाजा को एक बड़ा बोलते हैं - बैंगलुरु में एक युवा संघरक को संबोधित करते हैं देश में एक युवा संघरक को लोकतंत्र के लिए अपनी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि दिया का सामना रही है।

जब्बाबुल मुजाहिद ने कहा कि दिया का सामना रही है। अपनी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि दिया का सामना रही है।

प्राकिस्तानी मीडिया के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय ख्वाजा को एक बड़ा बोलते हैं - बैंगलुरु में एक युवा संघरक को संबोधित करते हैं देश में एक युवा संघरक को लोकतंत्र के लिए अपनी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि दिया का सामना रही है।

जब्बाबुल मुजाहिद ने कहा कि दिया का सामना रही है। अपनी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि दिया का सामना रही है।

प्राकिस्तानी मीडिया के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय ख्वाजा को एक बड़ा बोलते हैं - बैंगलुरु में एक युवा संघरक को संबोधित करते हैं देश में एक युवा संघरक को लोकतंत्र के लिए अपनी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि दिया का सामना रही है।

जब्बाबुल मुजाहिद ने कहा कि दिया का सामना रही है। अपनी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि दिया का सामना रही है।

प्राकिस्तानी मीडिया के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय ख्वाजा को एक बड़ा बोलते हैं - बैंगलुरु में एक युवा संघरक को संबोधित करते हैं देश में एक युवा संघरक को लोकतंत्र के लिए अपनी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि दिया का सामना रही है।

जब्बाबुल मुजाहिद ने कहा कि दिया का सामना रही है। अपनी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि दिया का सामना रही है।

प्राकिस्तानी मीडिया के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय ख्वाजा को एक बड़ा बोलते हैं - बैंगलुरु में एक युवा संघरक को संबोधित करते हैं देश में एक युवा संघरक को लोकतंत्र के लिए अपनी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि दिया का सामना रही है।

जब्बाबुल मुजाहिद ने कहा कि दिया का सामना रही है। अपनी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि









# इन कारणों से अक्सर बेहोश हो जाते हैं लोग



क्या आपने कभी सोचा है कि बेहोशी के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? हम आपने आस - पास अक्सर ऐसा देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो पूरी तरह से मिट्टि और स्वस्थ दिख रहा है लेकिन अचानक बिना किसी कारण वो आपने बेहोश होने लगता है। बेहोशी जो मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है हालांकि बेहोशी के कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे कारक हैं जो इनके लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। ये कुछ कारक हैं जो बेहोशी के कारण हो सकते हैं-

**लो ब्लडप्रेश्न:** बेहोशी का मैन कारण लो ब्लडप्रेश्न बताया जाता है यह आमतौर पर विशेष रूप से उन लोगों को ज्यादा होता है जो 65 से अधिक आयु वांगे होते हैं।

**निर्जलीकरण:** जबकि शरीर निर्जल हो जाता है, आपके खून में तरल परायी की मात्रा कम हो जाती है और ब्लड प्रेशर में कमी हो जाती है। इससे बेहोशी का खतरा बढ़ जाता है।

**मध्येह:** आप एक मधुमेह रोगी हो तो आपके बेहोशी के चासेज ज्यादा हैं क्योंकि डायबेटिक होने पर आपके शरीर आपने खोना चाहता है।

**दिल की बीमारी:** दिल की बीमारी भी बेहोश होने पर आपके दिमाग को होने वाली खन की समावृत्त व्याधि हो जाती है। बेहोशी के इस प्रकार के लिए मेडिकल टर्मोलॉजी में कार्डियक सिंनकॉप कहा जाता है।

## डिमेंशिया के खतरे को कम करती है नियमित कसरत



नियमित रूप से कसरत करने के कई फायदे होते हैं। इससे शरीर को युक्त-दुरुस्त रखने में मदद भी मिलती ही है। एक व्यायाम जीवनशीली अपनाने में भी यह योग्यता कारण होता है। एक व्यायाम जीवनशीली अपनाने से न केवल हमारा मरिंस्क रसियर रहता है बल्कि डिमेंशिया जीवी भूमिका वाली बीमारी का खतरा भी कम हो जाता है। यहुँ पर किए गए एक नए अध्ययन में पाया गया कि कसरत शरीर में एक मर्मतपूर्ण प्रौदीन की उपचारता बढ़ा सकती है। यह प्रौदीन मरिंस्क को साक्षिय करने के साथ ही (चुरो) तत्रिका से जुड़ी बीमारियों के खतरे को कम करता है। अध्ययन में पाया गया कि यहुँ पर किए गए नए कार्यक्रम के द्वारा यह अपनी भूमिका वाली बीमारी नहीं होती है।

**दालचीनी**

दालचीनी सिर्फ गर्म मसाला ही नहीं, बल्कि एक जड़ी-बूटी भी है।

यह एक ऐसी चीज़ होती है।

करने की बहुत अच्छी दवा है।

करने की बहुत अच्छी